



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]  
No. 55]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 1994/चैत्र 21, 1916  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 1994/CHAITRA 21, 1916

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 अप्रैल 1994

सं. 5(12)—संस्था-III/93—भारत सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की परि-  
लब्धियों के ढाँचे में हुए परिवर्तनों पर पिछले कुछ समय से विचार करती रही है। 1986  
में पिछले वेतन आयोग द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट के समय में लेकर परिस्थितियों में अनेक  
तरह के परिवर्तन भी हुए हैं। तदनुसार 5वां केंद्रीय वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय  
किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

- (i) अध्यक्ष
- (ii) सदस्य
- (iii) सदस्य-सचिव

न्यायमूर्ति एस. आर. पांडेयन  
प्रो. सुरेश तेंदुलकर  
श्री एम.के. काव

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

- (क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे और सेवा-शर्तों को संचालित करने वाले ऐसे सिद्धांत तैयार करना जो वित्तीय पहलुओं से संबंधित हों ।
- (ख) निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध नभय लाभों को ध्यान में रखते हुए परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करना और ऐसे परिवर्तनों का मुद्दा देना जो वांछनीय और व्यवहारिक हों :—
  - (i) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी—औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक;
  - (ii) अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मिक;
  - (iii) मशस्त्र सेनाओं के कर्मिक;
  - (iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मिक; और
  - (v) भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, दिल्ली के अधिकारी और कर्मचारी ।
- (ग) मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभों सहित पेंशनभोगियों के लिए उपयुक्त पेंशन संरचना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेंशन संरचना की जांच करना और उनसे संबंधित ऐसी सिफारिशें करना जो वांछनीय और व्यवहारिक हों ।
- (घ) उपर उल्लिखित वर्गों के कर्मचारियों को कार्य प्रणाली और काम करने के वातावरण के साथ-साथ वेतन के आकांक्षा, वर्तमान उपलब्ध भत्तों और वस्तु के रूप में लाभों की विविधता की जांच करना और प्रशासन में कार्य-कुशलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनावश्यक कामकाज को कम करते हुए तथा सरकारी मशीनरी के आकार को अनुकूलतम बनाते हुए उन्हें युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण करने के मुद्दा देना ।
- (ङ) अन्य संगत पहलुओं के साथ-साथ राज्य सरकारों आदि के अंतर्गत उपलब्ध वेतन-ढांचे और सेवा-निवृत्ति लाभों तथा देश की आर्थिक परिस्थितियों, केंद्रीय सरकार के संसाधनों और आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थान और राष्ट्रीय सुरक्षा और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंध को अपेक्षाओं के कार्यों पर मांगों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना ।

3. आयोग अपनी स्वयं की कार्यविधि तैयार करेगा और यह ऐसे मनाइकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जो वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे । वह ऐसी सूचना मंगा सकता है और ऐसा साध्य ले सकता है जो

वह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसी सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता प्रदान करेंगे जो कि आयोग को आवश्यक हो। भारत सरकार को विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संस्थाएं और अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग जैसा भी व्यवहार्य हो, अपनी सिफारिशें शीघ्र करेगा। यदि आयोग आवश्यक समझा तो वह सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर रिपोर्ट देने पर विचार कर सकता है।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित पक्षों को भेज दी जाए।

के. वेंकटेशन, सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 9th April, 1994

No. 5(12)E-III/93.—The Government of India have been considering for some time past the changes that have taken place in the structure of emoluments of Government employees over the years. Conditions have also changed in several respects since the last Pay Commission made its Report in 1986. Accordingly, it has been decided to appoint the Fifth Central Pay Commission comprising the following :—

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| (i) Chairman           | Shri Justice S.R. Pandian |
| (ii) Member            | Prof. Suresh Tendulkar    |
| (iii) Member-Secretary | Shri M.K. Kaw             |

2. The terms of reference of the Commission will be as follows :

- (a) To evolve the principles which should govern the structure of emoluments and those conditions of service of Central Government employees which have a financial bearing.
- (b) To examine the present structure of emoluments and conditions of service of the following categories of Government employees, taking into account the total packet of benefits available to them and suggest changes therein which may be desirable and feasible :—
  - (i) Central Government employees—industrial and non-industrial;
  - (ii) Personnel belonging to the All India Services;
  - (iii) Personnel belonging to the Armed Forces;

- (iv) Personnel of the Union Territories; and
- (v) Officers and employees of the Supreme Court of India and the High Court of Delhi.
- (c) To examine, with a view to having a proper pension structure for pensioners, the existing pension structure including death-cum-retirement benefits and make recommendations relating thereto which may be desirable and feasible.
- (d) To examine the work methods and work environment as also the variety of allowances and benefits in kind that are presently available to the aforementioned categories in addition to pay and to suggest rationalisation and simplification thereof with a view to promoting efficiency in administration, reducing redundant paper-work and optimising the size of the Government machinery.
- (e) To make recommendations on each of the foregoing having regard, among other relevant factors, to the prevailing pay structure and retirement benefits available under the State Governments, etc., economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of economic and social development, defence and national security and requirements of sound fiscal management.

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisers, institutional consultants and experts as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that State Government, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

4. The Commission will make its recommendations as soon as feasible. It may consider, if necessary, sending reports on any of the matters as and when the recommendations are finalised.

#### ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

K. VENKATESAN, Secy.